(क) दिल्ली दूरदर्शन में तदर्थ आधार पर काम करने वाले तृतीय श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या 30 दिसम्बर 1976 के वित्त मंत्रालय के आदेश संख्या 23011/6/75 ई (डी) के अनुसार वित्त मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त किये बिना तदर्थ कर्मचारी की सेवाएं एक वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ायी जा सकती हैं और मंजूरी जून के प्रारम्भ में ली जाती है ; और

(ग) क्या तदर्थ कर्मचारियों के मामले में वित्त मंत्रालय से मंजूरी ले ली गयी थी और अब तक कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) इस समय दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में श्रेणी -तीन का एक कर्मचारी 31 दिसम्बर, 1983 से तदर्थ आधार पर कार्य कर रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दूरदर्शन के लिये विदेशी फिल्मों के चयन हेतु समिति

3483. **श्री निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के लिये विदेशी फिल्मों के चयन हेतु एक समिति स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस समिति के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं ; और

(घ) इस समिति को, उसके उचित कार्यकरण हेतु, सरकार द्वारा क्या मार्ग निदेश जारी किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) से (घ) विदेशी टी० वी० कार्यक्रमों के चयन तथा संबंधित मामलों के बारे में दूरदर्शन को सलाह देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें श्रीमती पुपुल जयकर, अध्यक्ष, फेस्टिवल आफ इण्डिया, प्रो० यशपाल, परामशदाता, योजना आयोग, डा० नारायण मेनन अध्यक्ष, संगीत नाटक अकादमी और श्री एन०एस० गिल, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल हैं । समिति के सदस्यों का चयन कला, संस्कृति, विज्ञान और संचार के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के आधार पर किया गया है । समिति का मार्गदर्शन लोगों को सूचित करने, शिक्षित करने तथा उनका मनोरंजन प्रदान करने के दूरदर्शन के उद्देश्यों द्वारा किया जाता है ।

Establishments Allotted to Each P.F. Inspector in P.F. Organisation

3484. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of establishments covered by the Employees Provident Fund Scheme and the number of P.F. Inspectors employed in each Region of the P.F. Organisation ;

(b) the number of establishments allotted to each P.F. Inspector ;

(c) whether any complaint has been received from the employees organisations about the number of establishments allotted to each Inspector ; and

(d) if so, the steps taken to redress their grievances ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) to (d) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Provision of Creche Facility for Women Employees in EPF Organisation

3485. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the total number of women employees in E.P.F. Organisation and the number of centres where creches are provided for the women employees ;

(b) if no creches are provided, the reasons therefor ; and

(c) whether Government intend to provide creches at the various centres where more than 30 women are employed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Plant Load Factor in Thermal Units

3486. SHRI N. DENNIS :
SHRI B.V. DESAI :

Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Centre has directed the State Governments (State Electricity Boards) to achieve a minimum Plant Load Factor of 51 per cent from the thermal units commissioned during the year 1983-84 ; and

(b) if so, the details regarding the guidelines issued in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Interpretation of article 172

3487. SHRI K. MALLANNA :
SHRI N.E. HORO :

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any recommendation has been made to Government by the Election Commission that the Attorney General of India be consulted on the correct interpretation of Article 172 of the Constitution, on whether the term of a legislature be treated as having been extended once the President's rule is imposed in that State and whether flexibility in the length of Assembly's tenure is permissible; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : (a) The recommendation which was made to Government by the Election Commission that the Attorney General of India be consulted on the correct interpretation of article 172 of the Constitution was for seeking clarification as to whether the President's Proclamation under article 356 of the Constitution can be operated towards the end of the five-year term of